



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शुक्रवार, 20 जून, 2008 / 30 ज्येष्ठ, 1930

हिमाचल प्रदेश सरकार

[Authoritative English Text of this Department Notification No. Rev.B.F.(10)105/2008 dated 19.6.2008 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India.]

REVENUE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla – 171002, the 19th June, 2008

No.Rev.B.F.(10)105/2008.— In exercise of the powers conferred by clause (h) of section 5 of H P Ceiling on Land Holdings Act 1972, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to notify that the land to be held by M/s Ambuja Cements Limited situated in village Navagraon near Dabhota, Tehsil Nalagarh, District Solan, Himachal Pradesh for bonafide industrial use shall be exempted from the operation of the provisions of Himachal Pradesh Ceiling on Land Holdings Act 1972. Such an exemption shall be subject to implementation of 'Relief and Rehabilitation Scheme' of the company and the provisions of Relief and Rehabilitation Scheme shall be kept in view at the time of acquisition of land for the purpose. The detail of the land to be held by the said Company and notified to be exempted from the operation of the provisions of the Act *ibid* are given as under :

DETAIL OF LAND TO BE HELD BY THE M/S AMBUJA CEMENTS LIMITED :

Village	Khasra No.	Area		Purpose
		Bigha	Biswa	
Navagraon	73	11	17	Setting up of Grinding Unit
	74	05	16	
	125	05	13	
	126	00	16	
	1142/127	00	10	
	1143/127	03	10	
	129	01	16	
	130	01	02	
	131	01	03	
	132	00	16	
	133	00	16	
	1079/134	00	07	
	1080/134	01	14	
	136/1	00	16	
	136/2	01	17	
	136/3	00	17	
	136/4	01	05	
	140	00	16	
	141	00	06	
	142	00	08	
	143	01	00	
	144	03	17	
	145	00	15	
	146	07	02	
	147	01	00	
	148	01	08	
	149	00	07	
	150	03	12	
	151	00	17	
	152	02	09	
	153	02	08	
	154	01	08	
	155	00	17	

156	01	13	
157	00	19	
158	02	01	
159	03	18	
160	02	09	
161	00	04	
1147/162	05	07	
1148/162	03	09	
1149/162	02	14	
163	03	02	
164	01	19	
165	02	18	
166	01	18	
167	00	16	
168	07	03	
169	07	03	
170/1	00	01	
170/2	02	10	
171	02	17	
172	01	01	
173	03	08	
174	03	08	
175	02	08	
176	02	02	
177	03	15	
178	03	12	
179	10	10	
180	00	16	
181	04	18	
182	00	16	
183	04	16	
183/1	02	06	
184	01	17	
185	00	03	
186	03	14	
1226/187	04	10	
1227/187/1	00	06	
1227/187/2	00	19	
1228/187	00	17	
188/1	00	03	
188/2	00	17	
189	01	09	
190	03	06	
191	00	05	
192	01	14	
193	01	06	
194	00	09	
195	04	16	
1151/196	03	13	
1266/1153/196	01	13	
1267/1153/196	00	08	
1154/196	03	13	
1155/196	01	16	
1156/197/1	02	00	
1156/197/2	03	00	
1157/197	05	00	
1268/1158/197	01	03	
1269/1158/197	01	16	

	1159/197	02	09	
	198	00	04	
	1270/199	03	05	
	1271/199	03	04	
	200	01	03	
	201	00	15	
	202	00	13	
	203	01	03	
	204	02	00	
	205	00	05	
	206	01	16	
	207	01	00	
	208	01	16	
	209	01	04	
	210	01	14	
	211	04	02	
	212	00	14	
	213	00	19	
	214	00	17	
	215	00	17	
	1164/216	04	06	
	217	00	15	
	218	01	03	
	219	00	10	
	220	02	03	
	221	01	17	
	222	00	13	
	223	01	05	
	224	02	06	
	225	00	07	
	226	05	03	
	227	05	04	
	1167/228	05	07	
	1169/229	05	00	
	1170/229	00	15	
	236	11	05	
	260	00	19	
	261	00	19	
	262	01	00	
	263	01	00	
	264	01	17	
	265	01	16	
	266	00	18	
	267	01	02	
	1081/268	02	04	
	1082/268	00	19	
	1083/269	04	10	
	1084/269	02	12	
	270	00	16	
	271	01	11	
	272	03	12	
	273/1	00	11	
	273/2	04	08	
	273/3	01	02	
	273/4	03	05	
	1273/274	03	16	
	277	02	01	
	278	09	19	

	279	07	01	
	1087/285	10	04	
	1088/285	00	15	
	1231/286	01	00	
	1232/286	00	13	
	287	01	15	
	288	01	03	
	304	02	14	
	305	00	09	
	306	01	11	
	307	01	09	
	308	01	12	
	1274/309	03	18	
	1275/309	01	10	
	1276/310	01	10	
	1277/310	00	06	
	1278/311	01	15	
	1279/311	02	05	
	1280/312	03	05	
	1281/312	04	17	
	313	03	02	
	Kita (170)	398	01	

By order,
Sd/-
FC-cum-Secretary.

राजस्व विभाग

अधिसूचना

शिमला — 171002, 19 जून, 2008

संख्या: रैव0बी0एफ0(10)105/2008.— हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश भू-जोत अधिकतम सीमा अधिनियम 1972 की धारा 5 के खण्ड (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचित करते हैं कि मैसर्ज अम्बूजा सीमेंट लिमिटेड द्वारा वास्तविक औद्योगिक उपयोग के लिये मौजा नवा गांव समीप दभोटा, तहसील नालागढ़, जिला सोलन में धारित की जाने वाली भूमि को हिमाचल प्रदेश भू-जोत अधिकतम सीमा अधिनियम 1972 के उपबन्धों से छूट दी जाएगी। ऐसी छूट कम्पनी की “राहत एवं पुनर्वास योजना” (Relief and Rehabilitation Scheme) के कार्यान्वयन के दृष्टिगत होगी तथा सम्बन्धित भूमि का वास्तविक अधिग्रहण करते समय राहत एवं पुनर्वास योजना के प्रावधानों को भी ध्यान में रखा जाएगा। कथित कम्पनी द्वारा इस प्रकार धारित की जाने वाली भूमि और उपर्युक्त अधिनियम के उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट के लिए अधिसूचित की जाने वाली भूमि का विवरण निम्नलिखित प्रकार से है।

मैसर्ज अम्बूजा सीमेंट्स लिमिटेड द्वारा धारित की जाने वाली भूमि का ब्यौरा :

गांव	खसरा नम्बर	क्षेत्र		उद्देश्य
		बीघा	बिस्वा	
नवा गांव	73	11	17	ग्राइंडिंग यूनिट की स्थापना हेतु
	74	05	16	
	125	05	13	
	126	00	16	
	1142 / 127	00	10	
	1143 / 127	03	10	
	129	01	16	
	130	01	02	
	131	01	03	
	132	00	16	
	133	00	16	
	1079 / 134	00	07	
	1080 / 134	01	14	
	136 / 1	00	16	
	136 / 2	01	17	
	136 / 3	00	17	
	136 / 4	01	05	
	140	00	16	
	141	00	06	
	142	00	08	
	143	01	00	
	144	03	17	
	145	00	15	
	146	07	02	

	147	01	00	
	148	01	08	
	149	00	07	
	150	03	12	
	151	00	17	
	152	02	09	
	153	02	08	
	154	01	08	
	155	00	17	
	156	01	13	
	157	00	19	
	158	02	01	
	159	03	18	
	160	02	09	
	161	00	04	
	1147 / 162	05	07	
	1148 / 162	03	09	
	1149 / 162	02	14	
	163	03	02	
	164	01	19	
	165	02	18	
	166	01	18	
	167	00	16	
	168	07	03	
	169	07	03	
	170 / 1	00	01	
	170 / 2	02	10	
	171	02	17	
	172	01	01	
	173	03	08	
	174	03	08	
	175	02	08	
	176	02	02	
	177	03	15	
	178	03	12	
	179	10	10	
	180	00	16	
	181	04	18	
	182	00	16	
	183	04	16	
	183 / 1	02	06	
	184	01	17	
	185	00	03	
	186	03	14	
	1226 / 187	04	10	

	1227 / 187 / 1	00	06	
	1227 / 187 / 2	00	19	
	1228 / 187	00	17	
	188 / 1	00	03	
	188 / 2	00	17	
	189	01	09	
	190	03	06	
	191	00	05	
	192	01	14	
	193	01	06	
	194	00	09	
	195	04	16	
	1151 / 196	03	13	
	1266 / 1153 / 196	01	13	
	1267 / 1153 / 196	00	08	
	1154 / 196	03	13	
	1155 / 196	01	16	
	1156 / 197 / 1	02	00	
	1156 / 197 / 2	03	00	
	1157 / 197	05	00	
	1268 / 1158 / 197	01	03	
	1269 / 1158 / 197	01	16	
	1159 / 197	02	09	
	198	00	04	
	1270 / 199	03	05	
	1271 / 199	03	04	
	200	01	03	
	201	00	15	
	202	00	13	
	203	01	03	
	204	02	00	
	205	00	05	
	206	01	16	
	207	01	00	
	208	01	16	
	209	01	04	
	210	01	14	
	211	04	02	
	212	00	14	
	213	00	19	
	214	00	17	
	215	00	17	
	1164 / 216	04	06	
	217	00	15	
	218	01	03	

	219	00	10	
	220	02	03	
	221	01	17	
	222	00	13	
	223	01	05	
	224	02	06	
	225	00	07	
	226	05	03	
	227	05	04	
	1167 / 228	05	07	
	1169 / 229	05	00	
	1170 / 229	00	15	
	236	11	05	
	260	00	19	
	261	00	19	
	262	01	00	
	263	01	00	
	264	01	17	
	265	01	16	
	266	00	18	
	267	01	02	
	1081 / 268	02	04	
	1082 / 268	00	19	
	1083 / 269	04	10	
	1084 / 269	02	12	
	270	00	16	
	271	01	11	
	272	03	12	
	273 / 1	00	11	
	273 / 2	04	08	
	273 / 3	01	02	
	273 / 4	03	05	
	1273 / 274	03	16	
	277	02	01	
	278	09	19	
	279	07	01	
	1087 / 285	10	04	
	1088 / 285	00	15	
	1231 / 286	01	00	
	1232 / 286	00	13	
	287	01	15	
	288	01	03	
	304	02	14	
	305	00	09	
	306	01	11	

	307	01	09	
	308	01	12	
	1274 / 309	03	18	
	1275 / 309	01	10	
	1276 / 310	01	10	
	1277 / 310	00	06	
	1278 / 311	01	15	
	1279 / 311	02	05	
	1280 / 312	03	05	
	1281 / 312	04	17	
	313	03	02	
	किता (170)	398	01	

आदेश द्वारा,
हस्ता/—
वित्तायुक्त एवं सचिव।

लोक निर्माण विभाग

अधिसूचनाएं

शिमला-2, 16 जून, 2008

संख्या:पी.बी.डब्ल्यू(बी)एफ(5) 16/2008.— यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत गांव खनेरी, तहसील रामपुर, जिला शिमला में बस स्टैण्ड के लिए अपरोच सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस(30) दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग विन्टर फिल्ड, शिमला के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नम्बर	क्षेत्र(है0) में
शिमला	रामपुर	खनेरी	1102 / 20	0-02-00
			9	0-06-98
			10	0-53-18
			14	0-20-79
			1342 / 1103 / 20	0-84-00
			1218 / 19	0-00-25
			1360 / 1271 / 19	0-01-68
			1250 / 18	0-00-48
			1251 / 19	0-01-52
			1255 / 18	0-01-71
			1260 / 18	0-02-13
			1261 / 18	0-01-62
			1356 / 1262 / 18	0-20-51
			1254 / 19	0-01-98
			1259 / 1271 / 19	0-02-24
			1255 / 1262 / 18	0-00-65
		कुल	किता-16	2-01-72

शिमला-2, 13 जून, 2008

संख्या:पी.बी.डब्ल्यू(बी)एफ(5) 108/2007.- यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत गांव गुम्मा, तहसील कोटखाई, जिला शिमला में ठियोग-कोटखाई-हाटकोटी सडक के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस(30) दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग विन्टर फिल्ड, शिमला के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नम्बर	क्षेत्र (है0) में
शिमला	कोटखाई	गुम्मा	462	0-00-40
			598	0-14-32
		कुल	किता-2	0-14-72

संख्या:पी.बी.डब्ल्यू(बी)एफ(5) 95/2007 यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत गांव अणु, तहसील कोटखाई, जिला शिमला में ठियोग-कोटखाई-हाटकोटी सडक के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस(30) दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग विन्टर फिल्ड, शिमला के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नम्बर	क्षेत्र (है0) में
शिमला	कोटखाई	अणु	128	0-70-69
			148	0-17-22
			158	0-16-94
			154	0-25-22
			155	0-00-90
			156	0-03-49
			157	0-04-19
			129	0-02-18
			360	0-07-28
			365	0-07-46
		कुल	किता-10	1-55-57

शिमला-2, 13 जून, 2008

संख्या:पी.बी.डब्ल्यू(बी)एफ(5) 95/2007.- यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत गांव अणु, तहसील कोटखाई, जिला शिमला में ठियोग-कोटखाई-हाटकोटी सडक के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमत: अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस(30) दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग विन्टर फिल्ड, शिमला के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नम्बर	क्षेत्र (है0) में
शिमला	कोटखाई	अणु	128	0-70-69
			148	0-17-22
			158	0-16-94
			154	0-25-22
			155	0-00-90
			156	0-03-49
			157	0-04-19
			129	0-02-18
			360	0-07-28
			365	0-07-46
		कुल	किता-10	1-55-57

शिमला-2, 12 जून, 2008

संख्या:पी.बी.डब्ल्यू(बी)एफ(5) 92/2007.- यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत गांव ढांगवी कलां, तहसील कोटखाई, जिला शिमला में टियोग-कोटखाई-हाटकोटी सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमत: अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस(30) दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग विन्टर फिल्ड, शिमला के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नम्बर	क्षेत्र (है0) में
शिमला	कोटखाई	ढांगवी कलां	344	0-08-38
		कुल	किता-1	0-08-38

संख्या:पी.बी.डब्ल्यू(बी)एफ:(5) 105/2007.— यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत गांव वागडा दोयम, तहसील कोटखाई, जिला शिमला में ठियोग-कोटखाई-हाटकोटी सडक के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस(30) दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग विन्टर फिल्ड, शिमला के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नम्बर	क्षेत्र (है0) में
शिमला	कोटखाई	वागडा दोयम	36	0-01-86
		कुल	किता-1	0-01-86

शिमला-2, 12 जून, 2008

संख्या:पी.बी.डब्ल्यू(बी)एफ:(5) 96/2007.— यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत गांव कोकू, तहसील कोटखाई, जिला शिमला में ठियोग-कोटखाई-हाटकोटी सडक के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस(30) दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग विन्टर फिल्ड, शिमला के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नम्बर	क्षेत्र (है0) में
शिमला	कोटखाई	कोकू	7	0-32-46
		जोड	किता-1	0-32-46

शिमला-2, 16 जून, 2008

सं0पी0बी0डब्ल्यू0(बी0)एफ-5) 83/2008.- यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु गांव टिक्कर, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर में कुम्हारहट्टी-सराहां-नाहन सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस (30) दिन की अवधि के भीतर भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग शिमला, के समक्ष लिखित आपत्ति दायर कर सकता है।

विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा न0	क्षेत्र (विघा विस्वा)
सिरमौर	पच्छाद	टिक्कर	551 / 525 / 1	0-3
			553 / 526 / 1	0-2
			किता-2	0-5

शिमला-2, 16 जून, 2008

सं0पी0बी0डब्ल्यू0(बी0)एफ(5) 35/2008.- यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु गांव कसोल, तहसील सदर, जिला बिलासपुर में राष्ट्रीय उच्च मार्ग- 88 के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस (30) दिन की अवधि के भीतर भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग मण्डी, के समक्ष लिखित आपत्ति दायर कर सकता है।

विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नम्बर	बीघा-बिस्वा
बिलासपुर	सदर	कसोल	437 / 1 / 1	1-7
		कुल जोड	किता-1	1-7

सं0पी0बी0डब्ल्यू0(बी0)एफ0-(5) 361/2007.- यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु गांव गौडी घुलाणु/374 तहसील सरकाघाट, जिला मण्डी में जोगिन्द्रनगर-सरकाघाट-घुमारवीं राज्य उच्च मार्ग के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस (30) दिन की अवधि के भीतर भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग मण्डी, के समक्ष लिखित आपत्ति दायर कर सकता है।

विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नम्बर	क्षेत्र (हेक्टर)
मण्डी	सरकाघाट	गौडी घुलाणु/374	125 /1	0-00-32
			131 /1	0-00-06
			128 /1	0-00-20
			127 /1	0-00-49
			157	0-00-18
			159 /1	0-00-38
			162 /1	0-00-95
			154 /1	0-00-21

			153 / 1	0-00-58
			138 / 1	0-00-05
			147 / 1	0-00-13
			940 / 142 / 1	0-00-02
			944 / 941 / 142 / 1	0-00-07
			945 / 941 / 142 / 1	0-00-05
			141 / 1	0-00-05
			143	0-02-68
			146	0-01-60
			148	0-00-45
			344 / 1	0-00-09
			345 / 1	0-00-05
			358 / 1	0-00-77
			357 / 1	0-00-08
			952 / 360 / 1	0-00-33
			953 / 360 / 1	0-00-24
			359	0-00-62
			361 / 1	0-00-18
			362 / 1	0-00-32
			363 / 1	0-00-12
			364 / 1	0-00-14
			394 / 1	0-00-29
			395 / 1	0-00-33

			396 / 1	0-00-67
			410 / 1	0-00-40
			410 / 2	0-00-37
			955 / 411 / 1	0-00-11
			956 / 413 / 1	0-00-04
			957 / 413 / 1	0-00-54
			421 / 1	0-00-08
			422	0-00-05
			422 / 1 / 1	0-00-24
			423 / 1	0-00-45
			424 / 1	0-00-16
			435 / 1	0-00-24
			436 / 1	0-00-27
			437 / 1	0-00-77
			438	0-01-76
			439	0-00-81
			440 / 1	0-00-28
			445	0-00-10
			446	0-00-14
			448 / 1	0-00-56
			455 / 1	0-00-27
			457 / 1	0-00-52
			458 / 1	0-00-30

			459 / 1	0-00-20
			460 / 1	0-00-28
			461 / 1	0-00-22
			467 / 1	0-00-22
			468 / 1	0-00-26
			469 / 1	0-00-06
			470 / 1	0-00-04
			471 / 1	0-00-04
			472 / 1	0-00-06
			473 / 1	0-00-12
			518 / 1	0-00-06
			524 / 1 / 1	0-00-07
			149	0-00-32
			150	0-00-63
			151	0-00-93
			156	0-00-36
			524 / 2 / 1	0-00-03
		कुल जोड	किता - 71	0- 25-06

आदेश द्वारा,
हस्ता / -
सचिव।

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001

NOTIFICATIONS

16th June, 2008

No.HHC/Admn.3(208)/84-I.— One day's earned leave for 3.6.2008 and 4 days commuted leave on and with effect from 4.6.2008 to 7.6.2008 with permission to suffix Sunday falling on 8.6.2008 is hereby sanctioned, ex-post-facto, in favour of Shri Bhag Chand Sharma, Secretary, of this Registry.

Certified that Shri Bhag Chand Sharma has joined the same post and at the same station from where he had proceeded on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Shri Bhag Chand Sharma, would have continued to officiate the same post of Secretary but for his proceeding on leave.

17th June, 2008

No.HHC/Estt.3(111)/77-I.— 11 days earned leave on and with effect from 18.6.2008 to 28.6.2008 with permission to suffix Sunday falling on 29.6.2008 is hereby sanctioned in favour of Shri J.D. Sharma, Assistant Registrar, of this Registry.

Certified that Shri J.D. Sharma is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Shri J.D. Sharma would have continued to officiate the same post of Assistant Registrar but for his proceeding on leave.

Shimla, the 18th June, 2008

No.HHC/GAZ/14-131/82-IV.— Hon'ble the Chief Justice is pleased to grant 9 days earned leave w.e.f. 20.6.2008 to 28.6.2008 with permission to suffix Sunday falling on 29.6.2008 in favour of Shri K.L. Sharma, Registrar (Rules), High Court of Himachal Pradesh, Shimla.

Certified that Shri K.L. Sharma is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Shri K.L. Sharma would have continued to hold the post of Registrar (Rules), High Court of Himachal Pradesh, Shimla, but for his proceeding on leave for the above period.

17th June, 2008

No.HHC/Admn.3(309)/90-I.— 10 days earned leave on and with effect from 19.6.2008 to 28.6.2008 with permission to suffix Sunday falling on 29.6.2008 is hereby sanctioned in favour of Shri Manohar Lal Sharma, Secretary, of this Registry.

Certified that Shri Manohar Lal Sharma is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Shri Manohar Lal Sharma would have continued to officiate the same post of Secretary, but for his proceeding on leave.

By order,
Sd/-
Registrar General.

ब अदालत श्री जे० सी० शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील श्री नयना देवी जी स्थित
स्वारघाट, जिला बिलासपुर, हि० प्र०

श्री भगत राम पुत्र श्री घनईया राम, गांव रोड़ जामण, डा० तरसूह, तहसील श्री नयना देवी जी, जिला
बिलासपुर (हि० प्र०)।

बनाम

आम जनता

विषय .— प्रकाशन इश्तहार बावत जन्म तिथि पंजीकरण जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम,
1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

एतद्वारा आम जनता व हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि श्री भगत राम पुत्र श्री
घनईया राम ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में एक आवेदन प्रस्तुत किया है कि उसकी सुपुत्री जय देई की
जन्म तिथि 26-12-1960 है जो ग्राम पंचायत रोड़ जामण में दर्ज नहीं है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना
चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति
को कोई उजर/एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 30-6-2008 को सुबह दस बजे
इस अदालत में अदालतन या वकालतन हाजिर होकर प्रस्तुत कर सकता है। बाद गुजरने मियाद तारीख कोई
उजर व एतराज काबले समायत न होगा तथा प्रकरण में अन्तिम आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 24-5-2008 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

जे० सी० शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील श्री नयना देवी जी स्थित स्वारघाट,
जिला बिलासपुर (हि० प्र०)।

ब अदालत श्री जे० सी० शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील श्री नयना देवी जी स्थित
स्वारघाट, जिला बिलासपुर, हि० प्र०

श्री जगदेव सिंह पुत्र श्री अमर सिंह, गांव व डा० मजारी, तहसील श्री नयना देवी जी, जिला बिलासपुर
(हि० प्र०)।

बनाम

आम जनता

विषय .— प्रकाशन इश्तहार बावत जन्म तिथि पंजीकरण जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम,
1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

एतद्वारा आम जनता व हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि श्री जगदेव सिंह पुत्र श्री
अमर सिंह निवासी मजारी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में एक आवेदन प्रस्तुत किया है कि उसके दोहता

कर्ण वीर की जन्म तिथि 22-5-1989 व दोहती किरणदीप कौर की जन्म तिथि 9-10-1992 है जो ग्राम पंचायत मजारी में दर्ज नहीं है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर/एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 30-6-2008 को सुबह दस बजे इस अदालत में असातन या वकालतन हाजिर होकर प्रस्तुत कर सकता है। बाद गुजरने मियाद तारीख कोई उजर व एतराज काबले समायत न होगा तथा प्रकरण में अन्तिम आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 2-6-2008 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

जे० सी० शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील श्री नयना देवी जी स्थित स्वारघाट,
जिला बिलासपुर (हि० प्र०)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी रामपुर बुशहर, जिला शिमला (हि० प्र०)

नम्बर मुकद्दमा: 3/08

तारीख दायर

तारीख फैसला

श्रीमती अंजली देवी पत्नी श्री ईश्वर सिंह, निवासी गांव खनेरी, डाकघर खनेरी, तहसील रामपुर बुशहर,
जिला शिमला (हि० प्र०) . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी।

प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती कागजात माल चक खनेरी, परगना सराहन, खाता नं० 11/24, तहसील रामपुर बुशहर, जिला शिमला (हि० प्र०)।

उपरोक्त प्रार्थीया ने हमारे समक्ष एक प्रार्थना-पत्र इस आशय से प्रस्तुत किया है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख चक खनेरी में अंजला देवी गलत दर्ज हुई है, जबकि उसका वास्तविक नाम अंजली देवी है। इसकी पुष्टि में प्रार्थीया ने नकल परिवार रजिस्टर संलग्न किया है जिसमें प्रार्थीया का नाम अंजली देवी लिखा है, सही है। प्रार्थीया का नाम राजस्व रिकार्ड चक रचोली में भी अंजली देवी दुरुस्त किया जाए।

इस आम जनता को इस इशतहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश द्वारा सूचित किया जाता है कि अंजली देवी जिसका नाम राजस्व अभिलेख में अंजला देवी है के स्थान पर अब प्रार्थीया के अनुरोध अनुसार अंजली देवी दर्ज राजस्व अभिलेख होने में यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 28-6-2008 को प्रातः 10.00 बजे उपस्थित न्यायालय आकर पेश करें अन्यथा कार्यवाही एकतरफा नियमानुसार अमल में लाई जाएगी।

हस्ताक्षर हमारे मोहर अदालत से आज 2-6-2008 को जारी हुआ है।

मोहर।

पी० एस० नेगी,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
रामपुर बुशहर, जिला शिमला, (हि० प्र०)।

कार्यालय कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, रोन्हाट, जिला सिरमौर (हि० प्र०)

ब मुकद्दमा :

श्री दीप राम पुत्र श्री मनी राम, ग्राम सिधोटी, उप तहसील रोन्हाट ।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

श्री दीप राम पुत्र श्री मनीराम ग्राम सिधोटी ने इस न्यायालय में ब्यान हल्फी सहीत एक प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसके पुत्री कुमारी श्वेता शर्मा का जन्म मिति : 2-4-2003 को व कुमारी प्रिति शर्मा का जन्म मिति: 13-5-2004 को तथा कुमारी सरोज का जन्म मिति : 19-03-2007 को हुआ हैं, परन्तु ग्राम पंचायत पनोग के पंचायती अभिलेख में दर्ज करने से छुट गई हैं । प्रार्थी उक्त तीनों पुत्रीयों के नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत पनोग के रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता हैं ।

अतः आम जनता व सम्बन्धित रिश्तेदारों को इस अदालती इश्तहार द्वारा सुचित किया जाता है कि अगर उपरोक्त बारे किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 12-7-2008 को प्रातः 10.00 बजे या इससे पूर्व अपने उजर या एतराज असागतन या बकालतन पेश कर सकता हैं । बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा और प्रार्थना-पत्र उपरोक्त पर आगामी कार्यवाही अमल में लाई जावेंगी ।

आज दिनांक 05-6-2008 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी हुआ ।

मोहर ।

हस्ता० /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं,
नायब तहसीलदार रोन्हाट,
जिला सिरमौर (हि० प्र०) ।

कार्यालय कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, रोन्हाट, जिला सिरमौर (हि० प्र०)

ब मुकद्दमा :

श्री प्रताप सिंह पुत्र श्री तुलसी राम, ग्राम चाकला, उप तहसील रोन्हाट ।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

श्री प्रताप सिंह पुत्र श्री तुलसी राम, ग्राम चाकला ने इस न्यायालय में ब्यान हल्फी सहित एक प्रार्थना पत्र दिया है कि उसके पुत्र रितिक का जन्म मिति 9-6-2003 को हुआ हैं, परन्तु ग्राम पंचायत रास्त के पंचायती रिकार्ड में उसका नाम व जन्म तिथि दर्ज नहीं है । प्रार्थी इसे ग्राम पंचायत रास्त के पंचायती रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता हैं ।

अतः आम जनता व सम्बन्धित रिश्तेदारों को इस अदालती इश्तहार द्वारा सुचित किया जाता हैं कि अगर इस बारे किसी को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 12-7-2008 को प्रातः 10.00 बजे या इससे पूर्व अपने उजर या एतराज पेश कर सकता हैं ।

यदि उपरोक्त वर्णित तिथि को किसी भी व्यक्ति अथवा सम्बन्धित रिश्तेदारों का कोई उजर या एतराज इस न्यायालय को प्राप्त नहीं होता हैं । तो प्रार्थना-पत्र उपरोक्त पर आगामी कार्यवाही कर दी जावेंगी ।

आज दिनांक 05-6-2008 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी हुआ ।

मोहर ।

हस्ता० /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं,
नायब तहसीलदार रोन्हाट,
जिला सिरमौर (हि० प्र०) ।

ब मुकद्दमा :

श्री भजन सिंह पुत्र श्री पनिया राम, ग्राम शंखोली, उप तहसील रोन्हाट ।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र बराए दुरुस्ती बारें :-

श्री भजन सिंह पुत्र श्री पनिया राम ग्राम शंखोली ने इस न्यायालय में ब्यान हल्फी सहित एक प्रार्थना पत्र दिया है कि श्रीमति उतमों देवी उसकी हकीकी पत्नी व बिनोद, निरंजना, पंकज व सन्दीप हकीकी बच्चे हैं, परन्तु ग्राम पंचायत शंखोली के पंचायती रिकार्ड में उपरोक्त सभी सदस्य उसके भाई श्री भवान सिंह पुत्र श्री पनिया राम ग्राम शंखोली के नाम दर्ज हैं । प्रार्थी इस गलती को दुरुस्त करवाना चाहता हैं ।

अतः आम जनता व सम्बन्धित रिश्तेदारों को इस अदालती इश्तहार द्वारा सुचित किया जाता है कि अगर उपरोक्त बारे किसी को कोई उजर या एतराज हों तो वह अपना उजर या एतराज असालतन या बकालतन मिति 12-7-2008 को प्रातः 10.00 बजे या इससे पूर्व पेश कर सकता हैं । बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा और प्रार्थना-पत्र उपरोक्त पर आगामी कार्यवाही अमल में लाई जावेंगी ।

आज दिनांक 05-6-2008 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी हुआ ।

मोहर ।

हस्ता0/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं,
नायब तहसीलदार रोन्हाट,
जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ।

गृह विभाग
(गृह-क अनुभाग)

अधिसूचनाएं

शिमला-171002, 2 फरवरी, 2008

संख्या:गृह(क)ख(14)-69/96-पार्ट.- हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा 50 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य पुलिस बोर्ड में तीन गैर-सरकारी सदस्यों के नामनिर्देशन हेतु निम्नलिखित से गठित चयन पैनल के गठन का आदेश देते हैं :-

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| (क) लोक आयुक्त, हिमाचल प्रदेश | अध्यक्ष; |
| (ख) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त | सदस्य; और |
| (ग) अध्यक्ष, राज्य लोक सेवा आयोग | सदस्य |

राज्य सरकार, अधिनियम की धारा 50 में जैसा उपबंधित है, प्रत्येक रिक्ति के विरुद्ध, 4 उपयुक्त व्यक्तियों की, उनके जीवन-वृत्त सहित, अल्प-सूची का उपबन्ध करेगी। पैनल अल्प-सूची में से चयन करेगा यदि पैनल, कारणों को संसूचित करते हुए, चयन करने में असमर्थ हो तो उस दशा में, राज्य सरकार उपयुक्त व्यक्तियों की एक अन्य अल्प-सूची का उपबन्ध करेगी। चयन पैनल, गैर-सरकारी सदस्यों के चयन हेतु,

अपनी पारदर्शी प्रक्रिया बनाएगी; और अल्प-सूची की प्राप्ति के 30 दिन की अवधि के भीतर अपनी सिफारिशें देगा ।

आदेश द्वारा,
एस0 विजय कुमार,
प्रधान सचिव ।

[Authoritative English Text of this Department Notification No. Home (A)B(14)-69/96-Part, dated as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution].

**HOME DEPARTMENT
(Home-A-Section)**

NOTIFICATIONS

Shimla-171002, 2008

No.Home (A)B(14)-69/96-Part.— In exercise of the powers conferred by Section 50 of the Himachal Pradesh Police Act, 2007, the Governor of Himachal Pradesh, is pleased to order the constitution of a Selection Panel for nomination of three non-official Members to the State Police Board consisting of following :-

- | | |
|--|------------------------|
| (a) the Lokayukta Himachal Pradesh | ... Chairman; |
| (b) the State Chief Information Commissioner | ... member; and |
| (c) the Chairman of the State Public Service | ... member Commission. |

As provided in Section 50 of the Act, the State Government shall provide a short-list of 4 suitable persons alongwith their bio-data against each vacancy. The Panel shall make its selections out of the short-list unless, for reasons to be communicated, the Panel is unable to make a selection; in that event the State Government shall provide another short-list of suitable persons. The Selection Panel shall evolve its own transparent procedure for selection of the Non-official Members; and shall make its recommendations within a period of 30 days of receipt of the short-list.

By order,
P.C. KAPOOR,
Principal Secretary.

[Authoritative English Text of this Department Notification No. Home (A)B(14)-69/96, dated 02-02-2008 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution].

Shimla-171002, 2nd February, 2008

No.Home (A) B (14)-69/96.— In supersession of this Department Notification of even number dated 17th November, 2006 and in exercise of the powers conferred by Section 48 read with Section 49 of the Himachal Pradesh Police Act, 2007, the Governor Himachal Pradesh, is

pleased to establish the HP State Police Board to facilitate the laying down of policies, evaluate performance and ensure the functional autonomy of the State Police Service. The State Police Board shall consist of:-

- | | |
|---|-----------------------------|
| (i) the Chief Minister | ... Ex-officio Chairperson; |
| (ii) the Leader of Opposition of the State Assembly Himachal Pradesh. | ... Ex-officio Member; |
| (iii) Chief Secretary to the Government of Himachal Pradesh | ... Ex-officio Member; |
| (iv) Principal Secretary (Home) to the Government of Himachal Pradesh | ... Ex-officio Member; |
| (v) Principal Secretary (Social Justice & Empowerment) to the Government of Himachal Pradesh | ... Ex-officio Member; |
| (vi) Principal Secretary (Finance) to the Government of Himachal Pradesh | ... Ex-officio Member; |
| (vii) Director of Prosecution | ... Ex-officio Member; |
| (viii) Director Forensic Science | ... Ex-officio Member; |
| (ix) Three persons of proven reputation for integrity and competence on the recommendations of the Selection Panel constituted under section 50 of the Act. | ... Non-official Members; |
| (x) The Director-General of Police | ... Member- Secretary. |

As provided in Section 48, the Board shall meet as often as deemed necessary but at least once in three months. The Board shall function in the manner as provided in Section 53 of the Himachal Pradesh Police Act, 2007.

2. As provided in Section 54 of the Act:-

(1) Notice for meetings of the Board shall be issued by the Member-Secretary at least 15 days before each meeting. Members wishing to raise an item shall send notice so as to reach the Member-Secretary at least 7 days in advance and items shall be taken up with the approval of the Chairman of the Board.

(2) All meetings shall be held in Shimla unless the Board decides otherwise. A record of proceedings of the Board shall be maintained by the Member- Secretary who shall cause them to be circulated, with the approval of the Chairman, within 15 days of each meeting.

(3) The quorum for a meeting of the Board shall be one-third of the total membership of the Board. In the absence of quorum, the meeting of the Board shall be adjourned to the same time on the next working day and no quorum shall be required for such adjourned meeting.

(4) The Board may devise its own procedure for transaction of business in accordance with provisions of this Act.

3. As provided in Section 55 of the Act:-

(1) The Board shall, within three months after the end of each financial year present to the State Government a report on the work done by it during the year as well on the performance of the State Police, alongwith the annual policing Sub-Plan for the next year as approved by the Board. The report shall mention all cases where its recommendations were either not accepted or not responded to in accordance with the provisions of this Act.

(2) The State Government shall cause each such report to be laid before the State Legislature not later than two months of its receipt alongwith an action taken report.

4. As provided in Section 52 of the Act, Non-official members of the Board shall be entitled for a sitting fee of Rs. 1000/- per day for effective sittings of the Board. TA/DA of non official members shall be paid by the Police Head Quarters in accordance with Govt. instructions vide OM No.Fin-C-B (7)-14/98 dated 10-2-1999, and as subsequently amended from time to time.

By order,
P.C. KAPOOR,
Principal Secretary.

शिमला-171002, 2 फरवरी, 2008

संख्या:गृह(क)ख(14)-69/96.- हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना, तारीख 17 नवम्बर, 2006 के अधिकमण में और हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा 49 के साथ पठित धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीति निर्धारण को सुकर बनाने, उपलब्धि (पालन) का मूल्यांकन करने और राज्य पुलिस सेवा की कृत्यिक स्वायत्तता को सुनिश्चित करने के लिए, हिमाचल प्रदेश राज्य पुलिस बोर्ड की स्थापना करते हैं ।

राज्य पुलिस बोर्ड निम्नलिखित में से गठित होगा:-

- | | |
|--|--------------------|
| (i) मुख्यमंत्री | पदेन अध्यक्ष; |
| (ii) हिमाचल प्रदेश राज्य विधान सभा में विपक्ष का नेता | पदेन सदस्य; |
| (iii) मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार | पदेन सदस्य; |
| (iv) प्रधान सचिव(गृह),हिमाचल प्रदेश सरकार | पदेन सदस्य; |
| (v) प्रधान सचिव (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता)
हिमाचल प्रदेश सरकार | पदेन सदस्य; |
| (vi) प्रधान सचिव (वित्त),हिमाचल प्रदेश सरकार. | पदेन सदस्य; |
| (vii) निदेशक, अभियोजनपदेन सदस्य; | |
| (viii) निदेशक, न्यायालयिक विज्ञान | पदेन सदस्य; |

- (ix) अधिनियम की धारा 50 के अधीन गठित चयन
पैनल की सिफारिशों पर सत्यनिष्ठा और सक्षमता के
लिए ख्याति प्राप्त तीन व्यक्ति गैर सरकारी सदस्य;
- (x) पुलिस महानिदेशक सदस्य सचिव;

धारा 48 में जैसा उपबंधित है बोर्ड जितनी बार आवश्यक समझे, उतनी बार, परन्तु तीन मास में कम से कम एक बार बैठक करेगा। बोर्ड हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा 53 में यथा उपबंधित रीति में कार्य (कृत्य) करेगा।

2. अधिनियम की धारा 54 में जैसा उपबंधित है —

(1) बोर्ड की बैठकों की सूचना सदस्य सचिव द्वारा प्रत्येक बैठक से कम से कम 15 दिन पूर्व जारी की जाएगी। किसी मद को उठाने के इच्छुक सदस्य इसकी सूचना इस प्रकार भेजेंगे ताकि यह सदस्य सचिव के पास 7 दिन अग्रिम में पहुंच जाए तथा मदों को बोर्ड के अध्यक्ष के अनुमोदन से उठाया जाएगा।

(2) यदि बोर्ड अन्यथा विनिश्चय न करें तो समस्त बैठकें शिमला में ही आयोजित की जाएगी। बोर्ड की कार्यवाहियों का अभिलेख सदस्य-सचिव द्वारा रखा जाएगा जो उन्हें प्रत्येक बैठक से 15 दिन के भीतर, अध्यक्ष के अनुमोदन से, परिचालित करवाएगा।

(3) बोर्ड की किसी बैठक की गणपूर्ति, बोर्ड की कुल सदस्यता के एक— तिहाई से होगी। गणपूर्ति की अनुपस्थिति में, बोर्ड की बैठक अगले कार्य दिवस पर उसी समय के लिए स्थगित की जाएगी तथा इस प्रकार स्थगित बैठक के लिए गणपूर्ति अपेक्षित नहीं होगी।

(4) बोर्ड इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार कारवार के संव्यवहार के लिए अपनी प्रक्रिया की प्रकल्पना कर सकेगा।

3. अधिनियम की धारा 55 में जैसा उपबंधित है —

(1) बोर्ड प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् तीन मास के भीतर अगले वर्ष के लिए बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित वार्षिक पोलिसिंग उप योजना सहित इसके द्वारा वर्ष के दौरान किए गए कार्य के साथ-साथ राज्य पुलिस के कार्य सम्पादन (उपलब्धि) पर रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा। रिपोर्ट में, समस्त मामले, जहां इसकी सिफारिशें या तो स्वीकृत नहीं की गई थीं या इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार प्रतिक्रिया नहीं दी गई थी, वर्णित होंगे।

(2) राज्य सरकार, की गई कार्रवाई की रिपोर्ट सहित, ऐसी प्रत्येक रिपोर्ट को इसकी प्राप्ति के दो मास अपश्चात् राज्य विधानमण्डल के समक्ष रखेगी।

4. अधिनियम की धारा 52 में जैसा उपबंधित है बोर्ड की प्रभावी बैठकों के लिए, बोर्ड के गैर-सरकारी सदस्य 1000/-रुपये प्रतिदिन बैठक फीस के हकदार होंगे। गैर-सरकारी सदस्यों को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता (टी0ए0/डी0ए0) पुलिस मुख्यालय द्वारा ओ0एम0संख्या:फिन-सी-बी(7)-14/98, तारीख 10-2-1999 और तत्पश्चात् समय-समय पर यथा संशोधित सरकारी अनुदेशों के अनुसार संदत्त किया जाएगा।

आदेश द्वारा,
पी0 सी0 कपूर,
प्रधान सचिव।